आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 46 अंक 51 (प्रति रविवार) इंदौर, 10 सितम्बर से 16 सितम्बर 2023 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

जी 20 में अपनी ताकत का लोहा मनवाया भारत ने...

समिट में भारत के प्रस्तावों को मिला सदस्य देशों का समर्थन, दुनिया में भारत का बजा डंका

मोदी ने ब्राजील को सौंपी जी 20 की अध्यक्षता

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को जी 20 समूह की अध्यक्षता सौंप दी। इस दौरान उन्होंने सिल्वा को पारंपरिक गैवल (एक प्रकार का हथौड़ा) सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नई वैश्विक संरचना में दुनिया की नई हकीकत को प्रतिबिंबित करने का आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकायों में सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है। ऐसे में दुनिया के बड़े और जिम्मेदार संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। यूएनएससी में अभी भी उतने ही सदस्य हैं, जितने इसकी स्थापना के समय में थे। इसका विस्तार होना चाहिए, यानी स्थायी देशों की संख्या बढऩी चाहिए।

जी-20 के दिल्ली घोषणा पत्र को इस लिहाज से सबसे कठिन दौर में आया ऐतिहासिक घोषणा पत्र कह सकते हैं। गौरतलब है कि पिछला जी-20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। बाली घोषणा पत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दे पर चीन और रूस दोनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस घोषणा पत्र को चीन और रूस की आपत्ति को शामिल करके ही अंतिम रूप दिया गया था। दिल्ली में आयोजित जी-20 की शिखर बैठक में जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूरी बनाई थी, उससे ऐसी चिंता थी कि कहीं यहां भी आम सहमति न बन पाए। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर और जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत के चेहरे के भाव देखने लायक थे। अमिताभ कांत ने इसके लिए अपने सहयोगी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। वहीं विदेश मंत्री ने बताया कि इस स्थिति तक आने में ब्राजील, तुर्किए आदि ने बड़ी सहायता की। भारत ने आम सहमति के लिए कई स्तरों पर काफी प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि

नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत के पास है। इन दो दिनों में आप सभी ने बहुत सारे सुझाव दिए, प्रस्ताव रखे। हमारा कर्तव्य है कि सुझावों की एक बार फिर से समीक्षा की जाए, ताकि यह देखा जा सके कि उनकी प्रगति को कैसे तेज किया जा सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि नवंबर के अंत में हम जी 20 का एक वर्चुअल सत्र आयोजित करें। हम इस शिखर सम्मेलन में तय किए गए विषयों की समीक्षा उस वर्चुअल सत्र में कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी वर्चुअल सत्र में जुड़ेंगे। इसके साथ मैं जी20 सत्र के समापन की घोषणा करता हूं।

ब्राजील ने भारत की सराहना की

लूला डी सिल्वा ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को आवाज देने के लिए भारत की सराहना की। ब्राजील आधिकारिक रूप से इस साल एक दिसंबर में जी20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब देशों की कर्ज की समस्या पर ध्यान देना होगा। दुनिया को भुखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी।

रूस-यूक्रेन को भी कूटनीति से साध लिया

नई दिल्ली डिक्लेरेशन के 13वें पैरे में लिखा है, हम सभी राज्यों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, बनाए रखने की अपील करते हैं। मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं। विभिन्न देशों के मध्य संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और संकटों के हल के हल के लिए प्रयास करने के साथ ही कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण हैं। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करने के अपने प्रयास में एकजुट होंगे। यूक्रेन में व्यापक एवं न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का समर्थन करने वाली सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहलों का स्वागत करेंगे। बशर्ते, ये सभी पहल, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी उद्देश्यों और सिद्धांतों को कायम रखें। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देना होगा।

'इंडिया' गठबंधन से सरकार चिढ़ गई इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है-राहुल

ओस्लो (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंसेज पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सरकार हमारे I.N.D.I.A गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है। इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है। उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है, उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां वे एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे G20 समिट खत्म होने के 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर को भारत लौटेंगे। भारत में निचली

जाति की आवाज दबाई जा रही-राहुल ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा, BJP और RSS भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही हैं। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं, जहां लोगों के साथ बदसलूकी किया जाए। भाजपा के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं-भाजपा की विचारधारा पर राहुल ने कहा कि मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा और न किसी हिंदू विद्वान से सुना कि आपको उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए, जो आपसे कमजोर हैं। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं। उनका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं।भारत में करोड़ों लोग असहज महसूस करते हैं-भारत में सिख समुदाय सहित 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसे ठीक करने की जरूरत है। ऐसे अल्पसंख्यक भी हैं, जो असहज महसूस करते हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं, जो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।

5जी के बाद अब भारत और अमेरिका 6जी पर मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली। 5जी के बाद भारत में अब जल्द ही 6जी को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसके लिए अमेरिका के साथ एमओयू साइन हुआ है। हालांकि इस समय पूरी दुनिया अब तेजी से 6जी की तरफ कदम बढ़ा रही है। यही वजह है कि अब भारत और अमेरिका 6जी टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच टेक्नीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। एटीआईएस के नेक्स्ट जी एलायंस और भारत 6जी एलायंस के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के तहत दोनों ही एलायंस 5जी और 6जी टेक्नोलॉजी के बेहतर विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों ने 6जी पर रिसर्च शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ी और महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। टीआईएस के नेक्स्ट जी एलायंस और भारत 6जी एलायंस के बीच साइन हुए एमओयू के तहत दोनों ही देश 6जी वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों देश नए मौकों को तलाशेंगे। पीएम मोदी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस समझौते का स्वागत किया है। एटीआईएस के नेक्स्ट जी एलायंस का मुख्य काम 6जी और उसके आगे की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अमेरिका को मजबूत करना है।

संपादकीय

जी-20 का शिखर सम्मेलन बनाम पर उपदेश कुशल बहुतेरे

जी-20 के शिखर सम्मेलन में भारत को घोषणा पत्र के एजेंडा को बनाने में सफलता हासिल हुई है। सर्वसम्मति से सभी 83 बिंदुओं पर घोषणा पत्र पर सहमति बना ली गई है। अफ्रीकी यूनियन को जी 20 का नया सदस्य बनाया गया है। वैश्विक पर्यावरण के लिए एक नया एलाइंस बनाने पर सहमति हो गई है। भारत जी -20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। घोषणा पत्र को लेकर सदस्य देशों के बीच में जो विवाद था।भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों का उपयोग करते हुए जो प्रयास किए। उसमें भारत को सफलता हासिल हुई। सभी 83 बिंदुओं पर सहमति बना ली गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यूक्रेन युद्ध के स्थान पर सारी दुनिया में स्थाई शांति का प्रस्ताव लाकर सहमति बनाई। वहीं परमाणु युद्ध की धमकी के मामले में रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा कहे गए शब्द, यह युद्ध का काल नहीं है। इसका उपयोग करते हुए परमाणु हमले को रोकने के लिए सहमति बनाई गई। भारत ने जी-20 देश की बैठक में चंद्रयान-3 मिशन के लिए भी भारत के लिए बधाई हासिल कर ली। यह भारत की सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए, दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनो का पालन करने का प्रस्ताव शामिल किया। निश्चित रूप से जी-20 के शिखर सम्मेलन में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं उनमें केवल चर्चा नही होनी चाहिए, सम्मेलन में जो निर्णय लिए जाए उनका अक्षरस पालन करने की जिम्मेदारी भी सदस्य देशों की होनी चाहिए। तभी इस तरीके की बैठको और सम्मेलन की सार्थकता होगी। जी-20 की बैठक में व्यक्तियों के अधिकार,धार्मिक प्रतीकों, पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध दुष्प्रचार का विरोध करते हुए यह कहा गया है की सारी दुनिया के देश, धर्म, आस्था और विश्वास स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार, एक दूसरे पर आश्रित सामाजिक संबंधों को मजबूत करने, धर्म या आस्था के आधार पर सभी प्रकार की अशुद्धता और भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई में सभी देशों की भूमिका होनी चाहिए। आतंकवाद को लेकर भी घोषणा पत्र में कहा गया है, कि सभी धर्म की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसे सबसे गंभीर खतरा बताया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार एक समग्र दृष्टिकोण और एक अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात कही गई है। आतंकवादी समूह की सुरक्षित पनाहगाह, आतंकवाद गतिविधियां संचालन की स्वतंत्रता, बिना रोकटोक आवाजाही, उनके वित्तीय और भौतिक मदद को रोकने के लिए भी प्रस्ताव में चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना और निर्णय को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकासशील एवं गरीब देश के हितों को लेकर भी चर्चाएं होंगी। बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका को लेकर भी जी-20 के शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। जी-20 का यह पहला शिखर सम्मेलन नहीं है, जी-20 के सम्मेलन में इसी तरह के निर्णय पहले भी लिए जा चुके हैं। यह सब कागजों और घोषणाओं तक सीमित रहते हैं। आम सहमति बनती है, लेकिन इसका कोई क्रियान्वय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता हो। ऐसा दिखता नहीं है।सारी दुनिया के देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और कर्ज की अर्थ व्यवस्था को लेकर सारी दुनिया के देशों के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सारी दुनिया के देश विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विकसित राष्ट्र लगातार कई दशकों से पर्यावरण को लेकर जो प्रस्ताव और कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए। उसका पालन नहीं किया गया। इसका खामियाजा गरीब और विकासशील देशों को लंबे समय से उठाना पड़ रहा है। चिंता जताना अलग बात है, उन चिंताओं का समाधान होना अलग बात है ।संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी संस्थाओं के होते हुए भी पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। इन सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कोई कारगर भूमिका साबित नहीं हुई है। समरथ को नहीं दोष गुसाई की तर्ज पर समर्थ देश अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसको रोकने का प्रयास और साहस अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में नहीं दिखा। नाही समर्थ देशों ने उनकी परवाह की। जिसके कारण एक बार फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हालात, दुनिया के सभी देशों के बीच में देखने को मिलाने लगे हैं। जी-20 का यह शिखर सम्मेलन एक सार्थक ,सफल सम्मेलन के रूप में दुनिया में एक इतिहास बनाये। जिन विषयों को शामिल किए गया है। उनमें जो भी निर्णय लिए जाएं, उनका पालन सभी देश पूरी ईमानदारी के साथ करें। दुनिया को एक नई दिशा और दशा इस शिखर सम्मेलन से मिले। यह सम्मेलन सारी दुनिया के लिए एक उपदेश की तरह ना हो। सभी देश लिए गए निर्णय का ईमानदारी के साथ पालन करें। सारी दुनिया के देशों में स्थाई शांति स्थापित हो। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित सम्मेलन तभी सफल होगा और विश्व बंधुत्व की भावना सभी देशों के लिए हितकारी रूप में सामने आएगी।

संसद के सत्र पर इतना रहस्य क्यों ? क्या सोच रहे हैं मोदी ?

श्रवण गर्ग

अठारह से 22 सितंबर तक आहूत किए गए संसद के विशेष सत्र को प्रधानमंत्री द्वारा उनके दूसरे कार्यकाल के अंतिम पंद्रह अगस्त पर लाल क़िले से अत्यंत विश्वासपूर्वक की गई घोषणा के साथ जोड़कर देखा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मोदी ने कहा था अगले साल भी लाल क़िले से तिरंगा वे ही फहराएँगे । लाल क़िले से जी-20 तक का घटनाक्रम इसी ओर इशारा करता है कि चुनाव चाहे जब भी हों प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहने वाले हैं। यानी विपक्षी गठबंधन ढ्हछ्ढ्ढ चाहे जो कर ले। प्रधानमंत्री रहस्य की परतों के बीच जीते और शासन चलाते हैं। कहा जाता है कि अपने इर्द-गिर्द जो आभामंडल वे बनाए रखते हैं उसकी परतों के पार कोई झांक नहीं पाता, उनके सबसे नज़दीक माने जाने वाले सहयोगी भी नहीं ! वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के कॉरिडोर के भव्य लोकार्पण समारोह के छाया चित्रों को गूगल पर खोजिए। 13 दिसंबर 2021 को रेवती नक्षत्र में दिन के 1.37 बजे से 1.57 तक के शुभ मुहूर्त में कॉरिडोर के लोकार्पण से पूर्व जब उन्होंने गंगा माता में डुबकी लगाकर उसकी पूजा की तब भी वे ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्रों से आच्छादित थे।

वाराणसी से नामांकन भरते समय 'न मैं आया, न मुझे भेजा गया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है' का उच्चार करने वाले चुनाव-प्रत्याशी नरेंद्र मोदी गंगा माँ की गोद में भी प्रधानमंत्री ही बने रहते हैं और तब भी जब वे फोटोग्राफरों की टीम की मौजूदगी में गांधीनगर में माँ (स्व) हीराबेन से भेंट और उनके साथ भोजन करते थे।

पूछा जा सकता है कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की तरह ही पहरों में क्यों है ? प्रधानमंत्री कार्यालय या लोकसभा सचिवालय विज्ञापनों के ज़रिए उसे अख़बारों में उस तरह क्यों नहीं प्रकाशित करवा देता जिस तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्राप्त हुई।उपलब्धियों की गाथाएँ जनता के पैसों से छपवा कर जनता के बीच ही प्रसारित की जातीं हैं ? पीएमओ या लोकसभा सचिवालय ऐसा नहीं करेगा ! कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी चाहें तो इस सिलसिले में एक और चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखकर विशेष सत्र के एजेंडे पर अपनी और विपक्ष की चिंताएँ व्यक्त कर सकतीं हैं। 'स्वतंत्रता दिवस' के दिन लाल क़िले से की गई प्रधानमंत्री की घोषणा को सुनने वालों में कई विदेशी राजनयिक भी थे। निश्चित ही दुनिया भर के इन राजनयिकों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सार चेतावनियों के साथ अपने-अपने शासनाध्यक्षों को लाल क़िले के परिसर से ही स्मार्ट फ़ोनों के ज़रिए भिजवा दिया होगा। सवाल यह है कि ऐसा दावा कि अगले साल भी तिरंगा झंडा वे ही फहराएँगे प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के अंतिम पंद्रह अगस्त (2018) के उद्बोधन में क्यों नहीं किया था ? दूसरे कार्यकाल के अंतिम पंद्रह अगस्त को ही क्यों किया ? क्या विशेष सत्र के रहस्यमय एजेंडे में ही सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं ? या इन सच्चाइयों से भी कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी न सिर्फ़ एक के बाद एक विधानसभा चुनाव हार रही है ,उपचुनावों में भी उसकी पराजय हो रही है। छह राज्यों की सात सीटों के लिए हुए उपचुनावों में सबसे महत्वपूर्ण नतीजा प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के निकट स्थित घोसी का है जहां मुख्यमंत्री योगी द्वारा हर संभव ताक़त और संसाधनों का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भाजपा भारी मतों से हार गई। यूपी की अस्सी लोकसभा सीटें तो भाजपा के लिए सत्ता की रीढ़ हैं ! उन पर आगे क्या होने वाला है ?

क्या मान लिया जाए कि घोसी में पराजय से सत्ता की रीढ़ यूपी के भी चटकने की शुरुआत हो चुकी है और संघ के मुखपत्र 'पाँचजन्य' की तरह भाजपा को लग गया है कि सिर्फ़ मोदी की छवि और हिंदुत्व के बल पर ही पार्टी फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी ? ज़ाहिर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे द्वारा (दो सितंबर को) थमाया गया सनातन धर्म पर हमले का मुद्दा घोसी के लिए हुए मतदान (पाँच सितंबर) में भाजपा के काम नहीं आया !

आख़िरी सवाल यह कि लोकसभा चुनावों में हार की आशंकाओं के चलते प्रधानमंत्री अगर किन्हीं कमज़ोर क्षणों में सत्ता का मोह त्याग केदारनाथ की उस चर्चित गुफ़ा में ध्यान लगाने का मन बना लें जहां वे 18 मई 2018 को फ़ोटोग्राफ़रों की टीम के साथ पहुँचे थे तो क्या ऐसा कर पाएँगे ? शायद नहीं ! निहित स्वार्थों की भक्त मंडली ने उनकी आँखों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताक़त (लोकतंत्र नहीं) बनाने का ऐसा काजल रोप दिया है कि वह उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगा। चाटुकार उद्योगपतियों का समूह वर्तमान हुकूमत को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा देगा। यह समूह बारीकी से नोंद ले रहा है कि राहुल गांधी उसके ख़िलाफ़ संसद और विदेशों यात्राओं (हाल में ब्रुसेल्स) में किस तरह के भाषण दे रहे हैं !

प्रधानमंत्री ने सत्ता को अपने लिए काम के नशे में तब्दील कर लिया है। जैसा गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं ''नरेंद्र भाई पिछले नौ सालों से बिना एक दिन की भी छुट्टी लिए रोज़ाना सत्रह घंटे काम करते हैं।' अतः समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने लंबे राजनीतिक जीवन में एक दिन के लिए भी विपक्ष में नहीं बैठा हो वह एक दिन के लिए भी सत्ता से बाहर कैसे रह सकता है !

संसद के विशेष सत्र का एजेंडा देश की नज़रों से दूर रहस्य की परतों में छुपा है। पीएमओ के अलावा कोई अन्य दावे से नहीं कह सकता कि 18 से 22 के बीच क्या होने वाला है ! 'मोदी हैं तो मुमकिन है' की तर्ज़ पर सोचा जाए तो सब कुछ संभव है ! मतलब कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के अब तक के (गुजरात और दिल्ली के) बाईस सालों के कार्यकाल को ध्यान में लाएँ तो मोदी ने कभी चिंता ही नहीं की कि उनके फ़ैसलों से जनता की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है ! उनकी नज़रें हमेशा विपक्षी दलों की ज़िंदगी पर पड़ सकने वाले असर पर ही केंद्रित रहीं !

आठ नवंबर 2016 की रात आठ बजे अचानक से घोषित की गई नोटबंदी और उसके चार साल बाद 24 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के दौरान घोषित किए गए 21 दिनों के 'लॉक डाउन' सहित तमाम आकस्मिक घोषणाओं के पहले और बाद के देश की कल्पना करें तो तस्वीर ज़्यादा यादा साफ़ नज़र आने लगेगी। मोदी सिर्फ़ कार्रवाई में यक़ीन करते हैं, परिणाम जनता के भाग्य पर छोड़ देते हैं।

क्या संसद के विशेष सत्र के दौरान या उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता कि किसी आकस्मिक परिवर्तन के ज़रिए निर्धारित समय पर चुनाव कराए बग़ैर भी लाल क़िले से अगले साल झंडा फहराने (या बाद)तक मोदी ही देश के मुखिया बने रहें ? विशेष सत्र की उलटी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। इस सोमवार को ग्यारह सितंबर है और अगले को अठारह सितंबर।

डीएवीवी के होस्टल्स के छात्रों को मिलेगा हैल्दी फूड

दर्जनभर से ज्यादा होस्टलों में बनाया जाएगा एक जैसा भोजन

इंदौर। *इंदौर। ए ग्रेड प्राप्त देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अपने होस्टलों में रहने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखेगी। इस सिस्टम के लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी के करीब दर्जनभर से अधिक होस्टलों में एक ही मेन्यू में एक जैसा भोजन बनने लगेगा। इसके मेन्यू में यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने सेहत और स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखा है। हालांकि यह सिस्टम अगले सत्र से अमल में लाया जाना बताया जा रहा है।*

यूनिवर्सिटी अधिकारियों के अनुसार नया मेन्यू स्वाद और स्वास्थ्य से भरपूर होगा। होस्टलों में रहने वाले स्टूडेंट्स अन्य जिलों और क्षेत्रों के होते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि वे यहां स्वस्थ्य रहकर पढ़ाई करें। उन छात्रों को अपने घरों से दूर रहने के बाद भी घर जैसा भोजन मिले इसलिए ये हैल्दी मेन्यू बनाया गया है। इसमें मौसमी सब्जियां, दाल (मसूर, तुअर दाल, मूंग) रोटी, चावल, दही, सलाद सभी कुछ रहेगा। सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज और मिलेट्स को शामिल किया जाएगा। मौसम के अनुसार दही, रायता आदि भी शामिल किया जाएगा। होस्टल के मेस में एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगवाया जाएगा। इस पर अगले दिन का मेन्यू लिखा जाएगा। इसका मकसद यह है कि यदि कोई छात्र बोर्ड पर लिखी हुई सब्जी नहीं खाता है तो वह उसमें बदलाव करवा सकता है। रविवार को विशेष मेन्यू के अनुसार मटर पनीर की सब्जी, एक मिठाई, पूरी परोसी जाएगी। जो छात्राएं होस्टलों में रहकर मेस में भोजन करेंगी उनसे 2500 रुपए और छात्रों से 2800 रूपए प्रतिमाह लिए जाएंगे। इसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है। वैकल्पिक रूप से छात्र शुल्क के साथ केवल दोपहर का भोजन और रात के खाने का विकल्प चुन सकते हैं।

स्टूडेंट्स से फीडबैक भी लेंगे

मेस में बने भोजन के स्वाद, क्वालिटी और अन्य चीजों के लिए स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लिया जाएगा। मेस में बनने वाले खाने के साथ सफाई के लिए भी प्रभारियों को स्वच्छता के मानक बनाने के निर्देश दिए हैं। सुबह-शाम रसोईघर की सफाई का भी कहा गया है। समय-समय पर इसका निरीक्षण होगा। इस संबंध में छात्रों से फीडबैक फार्म भी तैयार किए जाएंगे।

ई-रिक्शाओं के रूट तय नहीं, कहीं से भी ले रही सवारियां

इंदौर। *स्वच्छता के साथ शहर को ट्रैफिक में भी नंबर-1 बनाने का दावा प्रशासन करता है, लेकिन दावों की पोल शहर में दौड़ रहे ई रिक्शा खोल कर रख रहे हैं। रूट तय नहीं होने से ये मनमर्जी से पूरे शहर में फरटि भर रहे हैं। कई बार ये ट्रैफिक का भी कचूमर निकाल देते हैं। दूसरी ओर शहर में नियम कायदों को ताक पर रखकर बाइक टैक्सी भी खूब दौड़ रही हैं।*

पर्यावरण सुधार के लिए ई-व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में शहर में ई- रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। इन ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से रोजगार से भी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इन रिक्शा चालकों के लिए रूट तय नहीं किए हैं। जिससे ये वाहन राजबाड़ा जैसे सघन क्षेत्र में बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। शहर के प्रमुख चौराहा पलासिया, विजय नगर, भंवरकुआं, महूनाका, गंगवाल बस स्टैंड, बड़ा गणपति आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां ये बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं। इन रिक्शाओं के रूट तय नहीं होने से ये मनमर्जी से शहर में फरटि भर रहे हैं।

अब तो ओवर लोडिंग भी करने लगे-वैसे ई-रिक्शा के लिए पूर्व में गाइड लाइन जारी की थी। इस गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश थे कि रिक्शा में ओवर लोडिंग नहीं होगी। ड्राइवर अपनी सीट पर सवारी नहीं बैठाएंगे। मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस गाइड लाइन का पालन शहर में नहीं हो रहा है। ओवर लोडिंग तो आम बात है। क्षमता से अधिक सवार लेकर दौड़ रहे हैं। बाइक टैक्सी पर नहीं रोक बाइक टैक्सी को लेकर प्रदेशभर में विरोध हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी परिवहन विभाग ने अभी तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अवैध रूप से संचालित हो रही बाइक टैक्सी की अप्लीकेशन पर रोक लगाए जाने के लिए परिवहन विभाग ने साइबर सेल को पत्र भी लिख चुका है, लेकिनसाइबर सेल ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

क्यूआर कोड- वाहन और चालक दोनों की रक्षा करेगा

इंदौर। *सड़क और वाहन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए रक्षा क्यूआर कोड का लोकार्पण डीसीपी ट्रॉफिक मनीष कुमार अग्रवाल ने किया। विशेष अतिथि थे एडिशनल डीसीपी ट्रॉफिक अरविंद तिवारी, एसीपी ट्रॉफिक मनोज खत्री, स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल एवं यातायात पुलिस के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह।*

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीसीपी अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सडक़ दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए इसके रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं। इस संदर्भ में यातायात पुलिस, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण आदि विभाग मिलकर सडक़ दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को प्रतिवर्ष दस प्रतिशत कम करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में यातायात सुधार के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। तात्कालिक ट्रॉफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए भी कार्ययोजना बन रही है। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात सुधार के लिए सहभागी बनने और रक्षा क्यूआर कोड जैसे विकल्प अपनाने का आह्वान किया है।

प्रारंभ में हाईवे डिलाइट कंपनी, बैंगलुरू के डायरेक्टर राजेश ने बताया कि कंपनी 2015 से फास्टैग, जीपीएस ट्रैकिंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बीमा और आरएसए और रिफ्लेक्टिव टेप और अन्य उत्पादों सहित सडक़ सुरक्षा उत्पादों सहित राजमार्गों के किनारे सेवाएं प्रदान कर रही है। रक्षा क्यूआर कोड बनाने का कंपनी का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होकर देश के लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस रक्षा क्यूआर के माध्यम से नागरिकों को सडक़ दुर्घटना के मामले में आपातकालीन सहायता प्राप्त हो सकेगी साथ ही लावारिस वाहनों से नागरिकों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए वाहन स्वामी को तत्काल सूचना भी पहुंच सकेगी। अगर आपका वाहन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपके घर तक यह जानकारी मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएगी।

उन्होंने बताया कि यदि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मदद मिले तो भारत में हर साल 1.5 लाख लोगों के दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में से लगभग 50 प्रतिशत लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक लोग आपातकालीन सहायता के रूप में क्यूआर का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि 'रक्षा क्यूआर' वाहन मालिकों को हाईवे डिलाइट के साथ पंजीकरण करने और रक्त समूह, वाहन बीमा, चिकित्सा बीमा और पारिवारिक आपातकालीन विवरण सहित अपनी व्यक्तिगत जानकारी जोडऩे में मदद करता है। 'रक्षा क्यूआर' की इस वाहन अधिसूचना सुविधा का उपयोग दो-पहिया, चार-पहिया, व्यावसायिक वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत डायरेक्टर राजेश, स्टेट हेड वाजिद अली कुरैशी, स्टेट सेल्स हेड माजिद खान ने किया। अतिथियों ने क्यूआर कोड का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन रिमझिम विश्वकर्मा ने किया एवं अंत में वाजिद अली कुरैशी ने आभार व्यक्त किया।

भाजपा के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के सारे दांव फेल किया

मप्र में यादव, वैष्णव, जामवाल, मुरलीधर और शिव प्रकाश संभाल रहे अहम जिम्मेदारी

भोपाल। *मप्र में पांचवी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने रणनीति का ऐसा जाल बुना है, जिसके कारण कांग्रेस के सारे दांव फेल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में जहां सत्ता और संगठन पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व के पांच रणनीतिकार अपनी रणनीति से भाजपा की जीत की राह आसान कर रहे हैं। ये रणनीतिकार हैं भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, अजय जामवाल, मुरलीधर राव और शिव प्रकाश।*

गौरतलब है कि मप्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी जमीनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ता में वापसी के लिए राज्य में पांच जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मप्र विधानसभा चुनाव की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

सीएम शिवराज समेत मप्र भाजपा के सभी सीनियर नेता लगातार क्षेत्रों को दौरा कर रहे हैं। मप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए इस बार बाहरी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव से जुड़ा सारा मैनेंजमेंट इन्हीं पांच नेताओं के भरोसे हैं।

भूपेन्द्र यादव

भूपेन्द्र यादव, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। हालांकि इनकी राजनीति राजस्थान से शुरू हुई है। एमपी विधानसभा चुनाव में भूपेन्द्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। यादव को मोदी-शाह का करीबी माना जाता है।

अश्विनी वैष्णव

भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सह-चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वैष्णव राजस्थान के हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। एमपी में लगातार दौरे कर रहे हैं। चुनाव से जुड़ा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं।

अजय जामवाल

अजय जामवाल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। 2019 से मध्यप्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव हैं। जामवाल पर्दे के पीछे से भाजपा के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं।

मुरलीधर राव

मुरलीधर राव, मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रभारी हैं। तेलंगाना के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के पहले से राज्य में एक्टिव हैं। सरकार के कामकाज के साथ-साथ संगठन के कार्यशैली की भी समीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इनके पास अहम जिम्मेदारी है।

शिव प्रकाश

शिव प्रकाश सह-संगठन महामंत्री हैं। मध्यप्रदेश में पर्दे के पीछे से रणनीति तय करते हैं। सार्वजानिक मंचों पर कम ही दिखाई देते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2020 से ही एक्टिव हैं। इनके पास छह राज्यों की जिम्मेदारी है। शिवप्रकाश उत्तर प्रदेश से आते हैं।

यादव-वैष्णव सबसे अधिक सक्रिय-प्रदेश में भाजपा के बाहरी नेताओं की सक्रियता की बात करें तो दो नेता सबसे अधिक सक्रिय हैं। ये हैं चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव। चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का परिवार मूलतः हरियाणा के गुरुग्राम जमालपुर से हैं। बचपन से राजस्थान में रहे। सियासी जमीन भी राजस्थान है। हाल ही में प्रदेश का जिम्मा मिला। मोदी-शाह के करीबी हैं। लगातार भोपाल आकर सक्रिय हैं। सह चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी राजस्थान से हैं। हाल ही में इन्हें भी जिम्मेदारी दी। ये भी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शाह के करीबी माने जाते। वे लगातार मध्यप्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आइटी पर फोकस है।

भाजपा को एक और बड़ा झटका, पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल

मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। नर्मदापुरम के कद्दावर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने रविवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। सैकड़ों समर्थकों के साथ राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे पूर्व विधायक गिरिजा शंकर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हम बता दें कि गिरिजा शंकर शर्मा और उनके परिवार का नर्मदापुरम की राजनीति में खासा दबदबा है। गिरिजा शंकर दो बार भाजपा विधायक रह चुके हैं। तथा नर्मदापुरम के भाजपा विधायक एवं मप्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा सीतासरन शर्मा के बड़े भाई हैं। गिरिजाशंकर दो बार नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

अलग-अलग अंचलों में आदिवासी, ओबीसी और एससी के लिए आयोजन

सम्मेलनों के जरिए जातिगत समीकरण साधेगी कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज दो माह का ही समय रह गया है। ऐसे में भाजपा द्वारा खेले गए जातिगत कार्ड की काट के रुप में अब कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी अब जातिगत कार्ड खेलने की तैयारी शुरु कर दी है, जिसके तहत अब प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में सम्मेलन करने का तय किया गया है। जिस अंचल में जिस वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव है, उस अंचल में उस वर्ग के सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इनमें पार्टी के बड़े नेताओं के अलावा खासतौर पर वे नेता शामिल होंगे , जो सबंधित वर्ग से वास्ता रखते हैं। इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी पार्टी द्वारा संबधित वर्ग के ही नेताओं को दिया जाना तय किया गया है। दरअसल प्रदेश में तीन वर्ग ही बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। इन वर्ग का जिस भी दल को समर्थन मिल जाता है सकी सरकार प्रदेश में बनना तय हो जाती है। कांग्रेस ने तय किया है कि आदिवासी बाहुल झाबुआ में अनुसूचित जनजाति, भोपाल में पिछड़ा वर्ग का तो बुदेंलखंड अंचल में एससी वर्ग का सम्मेलन करने का तय किया गया है।

अहम बात यह है कि यह सभी सम्मेलन प्रदेश स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल इन सम्मेलनों के आयोजन की तारीखें तय की जानी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 230 में से 82 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें

से 47 अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 अनुसूचित जाति के लिए हैं। इसमें शहडोल, डिंडोरी, मंडला, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र शामिल हैं, और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, रीवा और रायसेन शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की 7.26 करोड़ आबादी में अनुसूचित जाति 15.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 21.1 प्रतिशत हैं। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग की संख्या करीब 50 फीसदी है। एसटी वर्ग का प्रभाव करीब 80 से अधिक सीटों पर माना जाता है। ओबीसी मतदाताओं का प्रभाव भी 100 से अधिक सीटों पर है। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस, दोनों आदिवासी और ओबीसी वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति ने तय किया है कि आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के सम्मेलन में झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन सहित अन्य जिलों के आदिवासी भाग लेंगे।

प्रदेश के कई जिलों में है ओबीसी का बड़ा प्रभाव-प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले महीने कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से अशोकनगर, गुना, शिवपुरी सहित अन्य जिलों के पिछड़ा वर्ग से जुड़े नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इसी तरह से अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, रायसेन, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी सहित अन्य जिलों में यादव समाज के नेताओं का प्रभाव है। यही कारण है कि अरुण यादव को इन्हीं जिलों में जन आक्रोश यात्रा की अगुआई करने का दायित्व भी दिया है। वहीं, विंध्य में ओबीसी के प्रभाव को देखते हुए कमलेश्वर पटेल को आगे बढ़ाया गया है। उन्हें चुनाव से संबंधित सभी समितियों में सदस्य बनाने के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति भी शामिल किया गया है।

इन्हें दी गई जिम्मेदारी-सम्मेलन की तैयारी का जिम्मा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को दिया गया है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. विक्रांत भूरिया इसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। इसी तरह से ओबीसी सम्मेलन की तैयारी का जिम्मा अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल को दिया गया है। भोपाल में प्रस्तावित ओबीसी सम्मेलन की तारीख प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा तय की जाएगी।

त्योहार पर ट्रेनों में लगेगा इकोनॉमी कोच, भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने लिया फैसला

भोपाल। त्योहार की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भोपाल रेल मंडल एक बार फिर एक दर्जन से अधिक स्पेशल रेल गाडियों का संचालन करने जा रहा है। इसके अलावा दस ट्रेनों में इकॉनोमी कोच लगाने की तैयारी है। यात्रियों के लिए त्योहार के मौके पर कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे का यह फैसला यात्रियों के लिए खर्च बढने वाला भी साबित होने वाला है। रेलवे के फार्मूले के अंतर्गत इकोनॉमी कोच और फेस्टिवल स्पेशल के नाम पर चलने वाली इन रेलगाडियों में सामान्य किराए के मुकाबले 20 से 25 फीसदी तक 'यादा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके अलावा तत्काल व आरक्षण श्रेणी में अलग-अलग कैटेगरी में भी जीएसटी सहित शुल्क अदा करना होगा।

वेटिंग लिस्ट की ये है लिमिट-पिछले साल मई में रेलवे ने नियम अपडेट करते हुए वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करने को लेकर एक लिमिट तय की थी। इसके तहत स्लीपर क्लास के लिए अधिकतम 200, थर्ड एसी के लिए 100, सेकेंड एसी के लिए 50 और फर्स्ट एसी के लिए 20 वेटिंग लिस्ट की लिमिट है। स्पेशल ट्रेनों में 300 तक की वेटिंग लिमिट है। इसके बावजूद रेलवे के टिकट काउंटरों पर ट्रेन में वेटिंग टिकट की तय लिमिट से दोगुने टिकट काटे जा रहे हैं।

सिंधिया के गढ़ में ताकत आजमाएगी बसपा

मप्र में खोई हुई ताकत पाने की कर रही है

भोपाल। एक बार फिर से प्रदेश में तीसरी सियासी ताकत के रूप में बसपा उभरने के प्रयासों में लग गई है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश के चुनाव का जिम्मा अपनी भतीजे को सौंप रखा है। दो माह बाद होने वाले चुनावों की तारीखों को भले ही एलान नही हुआ है , लेकिन बसपा ने भी अपने सात उम्मीदवार घोषित कर जता दिया है कि वह इस बार मप्र को लेकर गंभीर है। पार्टी में अब दूसरी सूची जारी करने के लिए विचार मंथन का दौर चल रहा है। उप्र में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाली बसपा की नजर अब मप्र पर है। बसपा सुप्रीमों चाहती है कि उनके पास इतनी सियासी ताकत हो जाए की प्रदेश में बगैर उनकी मदद के सरकार न बन सके।

यही वजह है कि बसपा विंध्य के अलावा श्रीमंत के गढ़ ग्वालियर -चंबल अंचल पर अपना फोकस किए हुए है। बसपा की नजर इस अंचल की करीब एक दर्जन सीटों पर है। दरअसल यह वो अंचल है, जहां पर बसपा का सर्वाधिक प्रभाव है। इस अंचल से पूर्व में भांडेर से इं. फूलसिंह बरैया तो गिर्द (भितरवार) से लाखन सिंह यादव बसपा के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। अगर बीते चुनाव को देखें तो इस अंचल की 33 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत महज एक ही सीट पर मिल सकी थी। इसमें भिंड से भाजपा के बागी संजीव सिंह कुशवाह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 69107 वोट हासिल कर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। अगर अंचल की अन्य सीटों की बात की जाए तो सबलगढ़ में को लाल सिंह 45689 , ग्वालियर ग्रामीण में कांग्रेस के बागी साहब सिंह गुर्जर को बसपा के टिकट पर 49516 मत, जौरा में मनीराम धाकड़ को 41014 , पोहरी में कैलाश कुशवाह 52736 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे । इसी प्रकार विजयपुर में बाबूलाल मेवरा (भाजपा के बागी) 35628 , सुमावली में मानवेंद्र गांधी 31331 , लहार में भाजपा के बागी बसपा प्रत्याशी अंबरीश शर्मा 31367 , मुरैना में बलवीर डंडौतिया 21149 , अंबाह में सत्यप्रकाश 22179 , भितरवार में बीनू पटेल 18728 , चंदेरी में भाजपा के बागी राजकुमार यादव 34302 , सेंवढ़ा में लाखन यादव ने 18006 मत पाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। बसपा के प्रदेश में तब कुल दो विधायक जीते थे, जिसमें भिंड से संजीव कुशवाह के अलावा पथरिया से रामबाई परिहार शामिल हैं। अब भिंड विधायक संजीव कुशवाहा भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

दो चुनावों में मिल चुकी हैं 11 -11 सीटों पर सफलता-बसपा के लिए 1993 व 1998 के चुनाव भाग्यशाली रहे थे, उन चुनावों में उसने 11-11 सीटें हासिल की थीं। ग्वालियर-चंबल संभाग में बसपा के टिकट पर जौरा में सोनेराम कुशवाह, सुमावली से ऐंदल सिंह कंषाना, मेहगांव से नरेश गुर्जर, डबरा से जवाहर सिंह रावत, सबलगढ़ से बूंदीलाल रावत, गिर्द से लाखनसिंह यादव, भांडेर से फूल सिंह बरैया, अशोकनगर से बलवीर सिंह कुशवाह विधायक रह चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 2008 के चुनाव में बसपा

ने 9 प्रतिशत वोट पाकर प्रदेश में 7 सीटें जीती थीं। जबकि वर्ष 2018 में उसे 5 प्रतिशत वोट मिले और 2 सीटें ही जीत सकी। 2020 में हुए उपचुनाव में उसे कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 5.75 प्रतिशत वोट पाकर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बसपा नेताओं का मानना है कि प्रदेश की करीब 70 सीटों पर अजा वर्ग का प्रभाव है। वर्ष 2018 में भाजपा-कांग्रेस के बीच जीत-हार का अंतर 0.6 प्रतिशत था। जबकि हमें 1.3 प्रतिशत वोट मिले थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा को 2008 के चुनावों में 7 सीटें मिलीं और वोट 9 प्रतिशत मिले। जबकि 2018 के चुनाव में भले ही उसे दो सीटों पर जीत मिली, लेकिन करीब 65 सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने 10 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। इसलिए अचंल में बसपा कई सीटों पर हार-जीत में अहम भूमिका निभाती है।

चार जोन में बांटा मप्र को-बसपा सूत्रों का कहना है कि चुनाव के लिए हमने अपनी रणनीति बनाई है। प्रदेश को चार जोन में विभक्त किया गया है। बसपा की पहली सूची जारी की जा चुकी है, जबकि दूसरी सूची पर मंथन चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसके लिए लगातार सक्रिय हैं, वहीं सूत्रों का कहना है कि बसपा की नजर कांग्रेस और भाजपा की सूची पर है। इन दलों की सूची आने के बाद वह कई सीटों पर अपना निर्णय करेगी। भाजपा-कांग्रेस के असंतुष्टों में से कई पर वह दांव लगाकर मैदान में उतारेगी। भाजपा-कांग्रेस के ऐसे अनेक नेता हैं, जिन्हें अपने दल से टिकट मिलने की उम्मीद कम दिख रही है, वे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। और प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही यह नेता बसपा का दामन थाम मैदान में उतरेंगे। फिलहाल बसपा अभी इंतजार करो की नीति अपनाए हुई है।

बसपा के लिए खास सीटें-बहुजन समाज पार्टी के लिए ग्वालियर-चंबल की 34 सीटों में से करीब एक दर्जन सीटें खास हैं और वह अपनी रणनीति के तहत इन पर फोकस किए हुए है। इन सीटों में ग्वालियर ग्रामीण, सबलगढ़, जौरा, भिंड, मेहगांव, श्योपुर, विजयपुर, दिमनी, अंबाह, लहार, भांडेर, करैरा, पोहरी, चंदेरी, सुमावली शामिल हैं।

आवास भू-अधिकार योजना का लाभ देने में सिंगरौली प्रदेश में सबसे आगे

भोपाल। जरूरतमंदों को आवास के लिए भूमि मुहैया कराने में सिंगरौली जिला प्रदेश में सबसे आगे है। अब तक सबसे अधिक जमीन का पट्टा सिंगरौली में आवंटित किया गया है। बात मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की कर रहे हैं। संभाग का सीधी जिला दूसरे और संभाग मुख्यालय रीवा तीसरे स्थान पर हैं। जबकि, सतना का स्थान सातवां है। राजस्व विभाग की ओर से उपलब्ध रेकॉर्ड के मुताबिक सिंगरौली में अब तक सबसे अधिक 31773 लोगों को योजना के तहत भूमि का पट्टा दिया गया है। जबकि,अंतिम निराकरण के लिए जिला स्तर पर पहुंचे आवेदनों की संख्या 111067 है। इसी प्रकार सीधी जिले में अंतिम निराकरण के लिए पहुंचे आवेदन की संख्या 49027 है। जबकि 16091 हितग्राहियों को भूमि का पट्टा दिया गया है। बात रीवा की करें तो वहां 115233 आवेदन अंतिम निराकरण को पहुंचे हैं। जबकि 12173 को पट्टा का आवंटन किया गया है।

भाजपा के पांच सांसदों को मिल सकता है टिकट!

पार्टी ने सांसदों से मांगी उनकी राय

भोपाल। मध्यप्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। सत्ताधारी भाजपा भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा में भी विधान सभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की तैयारी चल रही है। भाजपा हर हाल में सत्ता में वापस आना चाह रही है। इसके लिए हर तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। टिकट वितरण में भी एक एक सीट जीतने के लिए प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी मौजूदा सांसदों पर दांव लगा सकती है। जानकारी के अनुसार भाजपा विधानसभा में सांसदों को भी उतार सकती है। जानकारों की मानें तो भाजपा के पांच सांसदों को विधानसभा का टिकट मिल सकता है। प्रत्याशी की खोज में सांसदों के नाम चल रहे हैं। पार्टी ने सांसदों से विधानसभा चुनाव लडने को लेकर राय मांगी है। मजबूत प्रत्याशी नहीं मिलने पर चुनाव लडने को लेकर सासंदों से राय मांगी गई है। इसी कड़ी में नर्मदापुरम सांसद राव उदयप्रताप सिंह से भी राय मांगी गई है। उनकी पुरानी सीट तेंदूखेड़ा से चुनाव लडने को लेकर राय मांगी गई है। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। जैतपुर या अनूपपुर सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा है। इसी तरह सीधी सांसद रीति पाठक से भी राय मांगी गई है। उन्हें सीधी जिले में उतारने की तैयारी है। रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर को झाबुआ से भाजपा उतार सकती है। सतना सांसद गणेश सिंह को अमरपाटन से उतारने की चर्चा चल रही है। पार्टी हर हाल में सभी सीट जीतना चाहती है। पार्टी के इस निर्णय टिकट के नए दावेदारों को झटका लग सकता है।

ग्वालियर चंबल संभाग में जीतेंगे 25 सीट-गृहमंत्री-मध्यप्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। चुनावी साल में हार और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भिंड में बयान समाने आया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में 25 सीट जीतेंगे। पूरे मध्यप्रदेश में 150 से 'यादा सीट जीतेंगे। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में उल्टा काम करेंगे। लहार के अवैध किले को भी ढहाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार महाराज हमारे साथ जीत हमारी होगी। तमिलनाडु के सीएम के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के सतनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर कहा कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा अगर किसी और धर्म पर बयान बाजी की जाती तो सर तन से जुदा हो जाता। सनातन धर्म में संस्कृति है कि हम चींटी को भी नहीं मारते है। इतना ही नहीं रात हो जाने पर सनातनी पेड़ पौधों को नहीं छूते हैं, ऐसा है हमारा महान सनातन धर्म।

सबसे ज्यादा कमाई के लिए जानी जाती हैं ये बंगाली एक्ट्रेस

अगर आपसे बंगाली एक्ट्रेसेस के बारे में पूछा जाए, तो आप भी बिपाशा बसु, कोंकणा सेन शर्मा, अपर्णा सेन और शर्मिला टैगोर का नाम लेंगे। बंगाली टीवी इंडस्ट्री और सिनेमा की एक्ट्रेसेस के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी टीवी एक्ट्रेसेस भी हैं, जो बंगाली टीवी इंडस्ट्री में टॉप पर हैं। आज हम आपको बंगाली टीवी से ताल्लुक रखने वाली ऐसी कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे, जो एक्टिंग में ही नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी में भी बड़ी हीरोइनों को मात देती हैं। टीवी में अपने दम से नाम बनाने वाली ये एक्ट्रेसेस हाईएस्ट पेड हैं और लोग उनके दीवाने हैं।

अंनिदिता बोस : आपने अमेजन की मोस्ट वॉच्ड सीरीज पाताल लोक देखी है? अंनिदिता बोस को भी उस सीरीज में आपने देखा होगा। बंगाली टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अंनिदिता को कौन नहीं जानता है? टीवी सीरीयल बौ कोथा काओ में उनकी एक्टिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। एक्टर होने के साथ ही अंनिदिता एक आर्टिस्ट भी हैं। वह अपने एक एपिसोड के लिए 2.5 लाख रुपये लेती हैं।

उनकी फिल्म की फीस 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक है। अनिंदिता बोस की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है।

प्रियंका सरकार : प्रियंका सरकार ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल्स से की थी और आज वह इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2.1 मिलियन फॉलोअर हैं और वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। साल 2005 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। स्टार्स अनफोल्डेड के मुताबिक उनकी नेट वर्थ 8 करोड़ रुपये के पास है। वहीं वह फिल्म के लिए 15 से 35 लाख रुपये के आसपास चार्ज करती हैं

मनाली डे : एक्ट्रेस मनाली डे को इंस्टाग्राम पर 223K लोग फॉलो करते हैं और वह बंगाली टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने 1999 में बंगाली फिल्म काली आमार मां से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक नीर भंगा झोर से टेलीविजन पर कदम रखा और बौ कोथा काओ में मौरी के रूप में अपनी भूमिका के लिए बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। इतना ही नहीं, साल 2021 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी शुरू किया है। टेलिविजन के साथ-साथ फिल्मों में भी उन्होंने अपने काम से अपना नाम बनाया है।

मोनामी घोष : मोनामी घोष बंगाली टीवी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह न सिर्फ अपनी पावर पैक्ड एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि डांसिंग में भी उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मोनामी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और वह फैशनिस्टा के रूप में भी जानी जाती है। साल 2022 में उन्होंने सिंगर के रूप में भी अपना नाम बनाया। मोनामी को इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। टेलीविजन प्रोजेक्ट्स के साथ ही वह फिल्मों में भी बखूबी बैलेंस बनाकर चलती हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 10-12 करोड़ है। वह टीवी और फिल्मों के अलावा अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी काफी कमाती हैं।

संपूर्णा लाहिड़ी : संपूर्णा लाहिड़ी को बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। इंस्टाग्राम पर उन्हें 237K लोग फॉलो करते हैं। एक एक्टर होने के साथ ही वह एक प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने 2012 की फिल्म गोरे गोंडोगोल से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म एक्सीडेंट और पांच अध्याय में भी अभिनय किया।

शाहरुख की मां बनी 19 साल छोटी एक्ट्रेस

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शको को फिल्म बेहद पसंद आ रही है और सभी किंग खान की तारीफ कर रहे हैं। हर जगह किंग खान की फिल्म 'जवान' के ही चर्चे हो रहे हैं। देश से लेकर विदेश में फिल्म की तारीफ हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म बेहद शानदार कलेक्शन कर रही है। अपने ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने 75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और दो दिनों में ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस बीच फिल्म जवान में शाहरुख खान की मां का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में उनकी मां रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा उनसे 19 साल छोटी है। इसलिए रिद्धि डोगरा खूब सुर्खियां बटोर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। बता दें कि रिद्धि डोगरा अभी महज 38 साल की है और शाहरुख खान 57 साल के है। 'जवान' में रिद्धि डोगरा के किरदार को 'कावेरी अम्मा' का नाम दिया गया है। बता दें कि किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेश' में भी एक्ट्रेस किशोरी बलाल ने उनकी मां का रोल अदा किया था। वहीं, अब सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसको लेकर मजे लें रहे हैं और मीम्स शेयर कर रहे हैं। साथ ही यूजर्स का कहना है कि 'कावेरी अम्मा' पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। इतना ही नहीं रिद्धि डोगरा ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही इस मजाक पर वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है।

कॉटन साड़ी के साथ इन एक्सेसरीज को बनाएं

स्टाइल का हिस्सा

साड़ी हर भारतीय महिला का पसंदीदा परिधान है। इसकी गिनती एक वर्सेटाइल आउटफिट में होती है, क्योंकि इसे केजुअल्स से लेकर ऑफिस व पार्टीज आदि में आसानी से कैरी किया जा सकता है। यूं तो साड़ी में आपको कई तरह के कलर से लेकर प्रिंट्स व स्टाइल मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने

लुक को पूरी तरह से बदलना चाहती हैं तो आपको इसके फैब्रिक पर भी ध्यान देना चाहिए। मसलन, पार्टीज के लिए जहां सिल्क को चुना जा सकता है, वहीं डे टू डे लाइफ में आप कॉटन को सलेक्ट करें। कॉटन की साड़ियां बेहद ही कंफर्टेबल होती हैं और इन्हें कभी भी स्टाइल किया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी

एक्सेसरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कॉटन साड़ियों के साथ कैरी करना एक अच्छा विचार हो सकता है-

पहनें चोकर

यूं तो कॉटन साड़ी को केजुअल्स में पहना जाता है। लेकिन अगर आप डे टाइम में किसी गेट टू गेदर या छोटी पार्टी का हिस्सा बन रही हैं तो ऐसे में कॉटन साड़ी को स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि, अपने लुक को पार्टी रेडी बनाने के लिए आप एक्सेसरीज को थोड़ा हैवी लुक दें। ऐसे में आप अपनी साड़ी के कलर को ध्यान में रखते हुए चोकर पहन सकती हैं। साथ ही, चोकर के साथ मैचिंग इयररिंग्स को भी अपने स्टाइल का हिस्सा बनाएं।

पहनें स्टेटमेंट इयररिंग्स

अगर आप कॉटन साड़ी के साथ मिनिमल एक्सेसरीज कैरी करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं तो ऐसे में आप स्टेटमेंट इयररिंग्स को पहन सकती हैं। आप अपने ब्लाउज के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए डैंगल्स इयररिंग्स से लेकर चांदबाली को स्टाइल कर सकती हैं।

स्टड को करें स्टाइल

कॉटन की साड़ियां ऑफिस लुक के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं। हालांकि, ऑफिस में कॉटन की साड़ी पहनते समय आपको अपनी एक्सेसरीज को लेकर अतिरिक्त सतर्क होना पड़ता है। ऑफिस में कॉटन की साड़ी में एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट करने के लिए आप स्टड पहन सकती हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल साइज स्टड ही पहनें। इसमें ओवर साइज्ड स्टड आपको एकदम डिफरेंट लुक देगा।

ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी

कॉटन साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा माना जाता है। खासतौर से, अगर आपने कॉटन साड़ी में व्हाइट या ब्लैक कलर कैरी करने का मन बनाया है तो उसके साथ ऑक्सीडाइज्ड नेकपीस से लेकर बैंगल्स को कैरी करें। इस लुक में आप कोहल आइज रखकर अपने स्टाइल को और भी एन्हॉन्स कर सकती हैं।

बेल्ट को करें स्टाइल

कुछ महिलाएं समझती हैं कि एक्सेसरीज में वह केवल इयररिंग्स, नेकपीस या बैंगल्स को ही कैरी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कॉटन साड़ी को एक ट्विस्ट के साथ और ट्रेन्डी तरीके से पहनना चाहती हैं तो उसके साथ बेल्ट स्टाइल करना भी अच्छा आइडिया हो सकता है। आप अपनी साड़ी के साथ या तो लेदर बेल्ट स्टाइल करें या फिर आप साड़ी के कलर के अनुसार बेल्ट को सलेक्ट कर सकती हैं।

जवां दिखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें

हर किसी की चाहत होती है कि वह हमेशा खूबसूरत दिखे लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है। खूबसूरत और जवां दिखने के लिए त्वचा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तेज धूप और बढ़ता प्रदूषण हमारी त्वचा की सारी चमक छीन लेता है। कुछ लोग त्वचा की देखभाल तो बहुत करते हैं लेकिन सही डाइट नहीं लेते, जिसके परिणामस्वरूप वे उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप जवान दिख सकते हैं।

पर्याप्त नींद- आपकी नींद का आपकी त्वचा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के साथ-साथ आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने में भी मददगार है।

ड्राई फ्रूट्स- ड्राई फ्रूट्स सेहत और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत 4-5 बादाम और 2-3 अखरोट के साथ कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी त्वचा को जवां बनाए रखने में मददगार हैं।

ब्लूबेरी- ब्लूबेरी में विटामिन ए, सी और एंथोसायनिन नामक एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये एंटी-ऑक्सीडेंट्स त्वचा को प्रदूषण और तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मददगार होते हैं साथ ही इसके सेवन से त्वचा में खुजली और जलन की समस्या से राहत मिलती है और सुंदरता बरकरार रहती है।

हरी पत्तेदार सब्जियां- हरी पत्तेदार सब्जियां पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के से भरपूर होती हैं। यह चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को दूर रखने में मददगार है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है।

इन आसान रेसिपी से बनाएं रेस्तरां स्टाइल पनीर लबाबदार

आज आपके लिए लेकर आए है पनीर लबाबदार की रेसिपी... कई लोगों को लगता है कि घर में होटल जैसा पनीर लबाबदार बनाना थोड़ा कठिन है, वास्तव में ऐसा नहीं है. यदि सही रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका पनीर लबाबदार होटल से कम स्वादिष्ट नहीं होगा. आइए आपको बताते है इसकी रेसिपी...

पनीर लबाबदार के लिए सामग्री-

तेल - 2 बड़े चम्मच
जीरा
लौंग - 4 से 5
दालचीनी
तेज पत्ता - 2
प्याज - 3
टमाटर- 4
खरबूजे के बीज - 2 बड़े चम्मच
काजू - 10 से 15
नमक -1 चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च - 3
गरम पानी - 1 कप
तेल -1 बड़ा चम्मच
मक्खन - 2 बड़े चम्मच
अदरक लहसुन का पेस्ट - 1 बड़ा चम्मच
हरी मिर्च - 2 से 3
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 बड़ा चम्मच
हल्दी पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच
धनिया पाउडर - 1 चम्मच
टमाटर प्यूरी - 3 बड़े चम्मच
कटी हुई शिमला मिर्च - 1
नमक - 1 चम्मच
गरम पानी - 1/2 कप
पनीर - 400 ग्राम
लाल मिर्च पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच
तेल
कसा हुआ पनीर- 50 ग्राम
चीनी - 1 चम्मच
गरम मसाला - 1/2 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी - 1 बड़ा चम्मच
ताजा क्रीम - 1 बड़ा चम्मच
कटा हुआ हरा धनिया

ऐसे बनाएं पनीर लबाबदार-

पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को बड़े टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को थोड़ी देर एक बाउल पानी में भिगो दें. फिर एक पैन गरम करें तथा इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालकर गरम करें. तेल के गरम होने पर इसमें जीरा, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता डालकर हल्का भून लें. खड़े मसाले भूनने के बाद इसमें प्याज को मोटा-मोटा काटकर डाल दें. जब प्याज हल्की सुनहरी हो जाए तो इसमें टमाटर, खरबूजे के बीज, काजू, नमक तथा कश्मीरी सूखी लाल मिर्च डालकर भून लें. जब मिश्रण भुन जाए तो इसमें 1 कप गर्म पानी डालकर मिश्रित करें फिर ढककर 10 मिनट तक पकाएं. जब ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए तो गैस बंद करके इसे ठंडा कर लें. ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी में डालकर पीस लें. याद रहे इसे ठंडा करके ही पीसना है. मसाला पीसने के बाद गैस पर एक कढ़ाही रखें तथा इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम करें इसमें थोड़ा सा मक्खन भी मिक्स कर दें. गरम करने के पश्चात् अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें. अब इसमें हरी मिर्चों को बारीक काटकर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह भून लें. मसाला भूनने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें तथा फिर 1 कप गरम पानी डालकर पकाएं. अब इसमें कटी हुई शमिला मिर्च तथा तैयार की हुई ग्रेवी डालकर अच्छी तरह पकाएं. ग्रेवी पकाने के बाद इसमें पनीर के टुकड़े डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर दें. अब इसमें 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा पनीर तेल में हल्का सेंक कर मिक्स कर दें. अब इसमें ताजी क्रीम तथा कटा हुआ हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिला लीजिए.आपका परफेक्ट पनीर लबाबदार पूरी तरह से तैयार है, अब आप इसका लुत्फ़ उठाएं।

एक सप्ताह से फूटी आजाद नगर में नर्मदा लाइन

लोग पानी के लिए परेशान, नहीं हो कर रहे सुधार

इंदौर। आजाद नगर मेन रोड पर नर्मदा लाइन एक सप्ताह से फूटी हुई है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां यह लाइन फूटी है वहां से चंद कदम दूर नर्मदा प्रोजेक्ट का आफिस है। उधर पानी नहीं मिलने से क्षेत्रीय रहवासियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लाइन दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

जानकारी अनुसार नई सड़क पर पानी की लाइन पहले भी कई बार फूट चुकी है। अभी काली पुलिया के पास की लाइन फूटी हुई है, जिसे ठीक करने का काम कई दिनों से जारी है, लेकिन लाइन अभी तक ठीक नही हुई है। मेन लाइन के फूटने से आजाद नगर, डेली कालेज, सिलीमन लाइन, फ़िरदौस नगर, नेतराम का बगीचे समेत मूसाखेड़ी क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वर्तमान में मूसाखेड़ी रिंग रोड़ से लेकर आजाद नगर फोर लेन सड़क बन रही है, जिस पर बार-बार पानी की लाइन फूट रही है। पहले भी मूसाखेड़ी में राम मंदिर के पास और नर्मदा प्रोजेक्ट के पास कई बार पानी की लाइन फूट चुकी है, जिससे लोग कई कई दिनों तक पानी के लिए परेशान होते रहे हैं। पानी की लाइन बार-बार इस तरह क्यों फूटती है इसका किसी अधिकारी के पास कोई सही जवाब नहीं है। सूत्रों के अनुसार यहां पर डाली गई मेन लाइन काफी पुरानी होकर खराब हो चुकी है और अब टंकी के पानी का दबाव सहन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण लाइन बार फूट जाती है। कई जगह खराब हो चुकी है नई सड़क-मूसाखेड़ी से आजाद नगर तक की ढाई किलो मीटर की फोरलेन सड़क का काम पिछले लगभग छह सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। एक और तो सड़क पूरी तरह से बन भी नहीं पाई है और दूसरी तरफ पानी की लाइन फूटने से सड़क इतनी जगह से खोदी जा चुकी है कि उसकी मजबूती लगभग बेकार हो चुकी है। हालांकि इस सड़क का काम दो कंपनी ने किया है एक कंपनी के कर्मचारियों का कहना है है कि हमनें सड़क बना दी है अब अगर नर्मदा की लाइन फूट रही है तो उसमे हम क्या कर सकते हैं।

12 और 13 सितंबर को रोजगार मेला आईटीआई में

इन्दौर। इंदौर संभाग के धार जिला रोजगार कार्यालय द्वारा जिले में रोजगार मेलों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धार में 12 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन शासकीय आई.टी. आय. केम्पस धामनोद में किया जायेगा। इसी प्रकार 13 सितंबर को शासकीय आई.टी.आई. केम्पस मनावर (खेडी) में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इन रोजगार मेलों में संस्था एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर पिथमपुर, ऑटो क्लस्टर (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) जिला धार मे (केवल अनुसूचित जाति पुरुष/महिला) महिमा प्योर स्पन पिथमपुर, एल.आय.सी. मनावर, व्ही कर्मशियल कम्पनी पीथमपुर, प्रतिभा सिंटेक्स कम्पनी पिथमपुर, शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड सेक्टर 3 पिथमपुर, लखानी रबर प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड पिथमपुर, महिमा फाईबर्स प्रा.लि. मि. पिथमपुर द्वारा भर्ती की जावेगी। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष, केवल बी.पी.एल कार्डधारी हो एवं योग्यता 5वीं से 12वीं, स्नातक, आई.टी.आई. एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण हो, अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ 11 बजे तक उपस्थित सकते हैं।

भाजपा की जनआशीर्वाद यात्रा के बैनर पोस्टरो पर कांग्रेस नेता की फोटो, कांग्रेस पहुंची थाने बीजेपी ने बताया पेंटर की गलती

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी की इंदौर संभाग की खंडवा से 6 सितंबर को शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा जिसे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था । जब बुरहानपुर जिले से होकर फिर से खंडवा के मांधाता में प्रवेश कर रही थी तब स्वागत में लगे बैनर पोस्टर को लेकर अजीबोगरीब विवाह पैदा हो गया जिसके चलते प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो गए, कांग्रेस नेताओं ने थाने कोर्ट जाने की धमकी दे डाली वहीं बीजेपी नेताओं ने गलती स्वीकार कर इसे पेंटरों की भूल बताया। दरअसल मामला उस समय गर्मा गया जब भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा के स्वागत में जगह - जगह लगाए बैनर पोस्टरों में कुछ बैनरों पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव और खंडवा जिले के प्रभारी कैलाश कुंडल का फोटो चस्पा कर दी गई । इसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय ओझा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास अच्छे नेताओं का टोटा है इसलिए हमारे नेताओं को प्रभावित करने के लिए वह ऐसी हरकतें कर रही है । ओझा ने कहा कि यदि यह मानवीय भूल से हुआ होता तो फोटो एक जगह नजर आती लेकिन ऐसा जान बुझकर किया गया है। सभी बैनरों पर हमारे नेता कैलाश कुंडल की तस्वीर लगी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत धनगांव थाने में कर दी है। हमारी मांग है कि मामले में पुलिस ऐक्शन ले। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे बैनर बनाने वाले की गलती बताया है । कांग्रेस के महासचिव और खंडवा प्रभारी कैलाश कुंडल ने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है ।

पीएम उषा योजना के लिए डीएवीवी ने भेजे दो कंपोनेंट प्रस्ताव

इंदौर। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रुसा योजना को जून-2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा के रूप में लॉन्च किया गया। प्रायोजित इस योजना के तहत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। इसी योजना के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 100 करोड़ और 20 करोड़ रु. के दो कंपोनेंट प्रस्ताव तैयार किए हैं। पीएम उषा योजना राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कोर्स व कार्यक्रम में बदलाव, टीचर ट्रेनिंग, फिजिकल व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता और रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए फंड प्रदान करती है। केंद्र सरकार के निर्देश पर डीएवीवी ने कंपोनेंट वन प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है।

मानसून विदाई की ओर तालाब अभी भी खाली

इंदौर। इस महीने के आखिर तारीख को मानसून विदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक सभी तालाब लबालब नहीं हुए हैं। यहां तक कि इंदौर का प्रमुख तालाब यशवंत सागर ही अभी करीब एक फीट खाली है। यही स्थिति अन्य तालाबों की भी है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में 30 सितंबर को मानसून की विदाई मानी जाती है। इस लिहाज से अब महज 20 दिन बाकी हैं। दूसरी और इंदौर का कोटा 37 इंच माना जाता है, जबकि इस साल मानसून की बेरूखी के चलते अभी तक महज 31 इंच बारिश हुई है। बारिश कम होने की वजह से तालाबों का जलस्तर भी काफी कम है। हालांकि, यह राहत की बात है कि कुछ तालाबों में इतना पानी आ गया है कि अगले वर्ष लोगों को जलसंकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी और जिन तालाबों में जल स्तर कम है, उन्हें लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

चैनल से नहीं पहुंचा पानी- तालाबों में पानी कम भरने का एक कारण इसके चैनलों से पानी कम पहुंचना भी बताया जा रहा है। दरअसल, नगर निगम के जल कार्य विभाग द्वारा हर साल लाखों रुपए खर्च कर बारिश से पहले विभिन्न तालाबों के केचमेंट एरिया में जिन चैनलों से पानी आता है, उन्हें गहरी करवाने एवं चैनल रूट से अतिक्रमण व अन्य अवरोधकों को हटाने का काम कराया जाता है। तालाबों का जल स्तर कम होने से यह साफ हो जाता है कि पानी के चैनलों की सफाई नहीं हुई, अवरोधक नहीं हटाए गए। लाखों रुपए पानी में बहा दिए।

तालाबों में कितने फिट पानी - शहर को जलापूर्ति में अहम भूमिका निभाने वाले यशवंत सागर से शुरूआत करें तो इसकी क्षमता 19 फिट है और अभी यहां जल स्तर करीब 18 फिट है। बड़ी बिलावली तालाब की क्षमता 34 फीट है और जलस्तर 25.2 फिर है। छोटी बिलावली तालाब की क्षमता 12 फीट है और अभी जलस्तर 8.9 फीट है। इसी प्रकार छोटा सिरपुर की क्षमता 13 फिट है और जलस्तर 12.5 फीट है, जबकि बड़ा सिरपुर की क्षमता 16 फीट है और यह अभी 13.8 फीट ही भराया है। इसी प्रकार, पीपल्यापाला तालाब की क्षमता 2 2 फीट है और जल स्तर 21 फीट है। इसके अलावा, लिंबोदी तालाब की क्षमता 16 फीट है, जबकि जलस्तर महज 2.7 फीट है।

लाल ईंट प्रतिबंध का मुद्दा आल इंडिया एसोसिएशन तक पहुंचा

इन्दौर। मध्यप्रदेश में सरकार ने शासकीय निर्माण कार्यों में ईंट भट्टों पर बनाई जाने वाली लाल ईंटों का प्रयोग प्रतिबंधित कर रखा है। राज्य सरकार के इस फरमान से प्रदेश के हजारों ईट निर्माता तो संकट में आ ही गए हैं, शासकीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। शासन ने लाल ईंट के बजाय फ्लायऐश से निर्मित ईंटों का प्रयोग शुरू करने के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों गुवाहाटी (असम) में आयोजित ऑल इंडिया ब्रिक्स एंड टाईल्स फेडरेशन नई दिल्ली की कार्यकारिणी की बैठक में म.प्र. ब्रिक्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर देशभर से आए ईंट निर्माताओं के संगठनों का ध्यानाकार्षण किया था, अब आल इंडिया एसो. ने राज्य की शिवराज सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। म.प्र. ब्रिक्स एसो. के प्रदेशाध्यक्ष रमेशचंद्र, प्रजापति, रमेश कश्यप एवं पन्नालाल कश्यप ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में शासकीय निर्माण कार्यों में ईंट भट्टों पर पकाई गई लाल ईंट का प्रयोग ही किया जा रहा है, किन्तु म.प्र. सरकार ने फ्लायऐश से निर्मित ईंटों का प्रयोग करने के आदेश देकर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)